

दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा की स्थिति खराब...

सरकारी स्तर पर उच्च शिक्षा में नीतिगत संकट का दौर

वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति बहुत खराब है। यह संकट वित्त पोषण, शिक्षा की गुणवत्ता और महत्ता की ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा खराब है। चाहे बात भारत की हो या अन्य दक्षिण एशियाई देशों की। हर देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत संकट की स्थिति बनी हुई है। इन देशों में अभी तक प्रभावी शिक्षा की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है।

वर्ष 2015 में सोशल साइंटिस्ट जर्नल के फरवरी अंक में बीजी तिलक का लेख हायर एजुकेशन इन साउथ एशिया - क्राइसिस एंड चैलेंजेज में बताया गया है कि दक्षिण एशिया में एक तरफ मालदीव जैसे छोटे देश हैं वहीं भारत की तरह विशाल राष्ट्र भी हैं। लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और भारत के बीच अंतर आंशिक ही है। इन देशों के बीच उच्च शिक्षा को लेकर एक जैसी समस्याएं हैं। सभी देश न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हैं बल्कि सभी की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत, औपनिवेशिक मूल्य व शासन पद्धति भी एक समान हैं। इतना ही नहीं कमोबेश सभी देशों की सरकारों की नजरों में शिक्षा पर खर्च प्राथमिकता सूची में नहीं है। यही कारण है कि शिक्षा की गुणवत्ता वैश्विक मानकों पर खरा नहीं उतरता। सोशल साइंटिस्टों की मानें तो दक्षिण एशियाई देशों में स्पष्ट शिक्षा नीति का अभाव है। जबकि इस क्षेत्र में विश्व की करीब 25 फीसद आबादी रहती है।

शिक्षा की नामांकन दर



भारत में सरकारी और निजी सहित सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय

दक्षिण एशियाई देशों में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इनमें सरकारी और निजी दोनों मिलाकर 785 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। करीब 200 विश्वविद्यालय पाकिस्तान और 131 विश्वविद्यालय बांग्लादेश में हैं। संख्या की दृष्टि से स्थिति संतोषजनक है लेकिन सौध और अनुसंधान के लिहाज से इनकी उपस्थिति वैश्विक स्तर पर न के बराबर है। वर्ष 2010 तक के आंकड़ों के हिसाब से उच्च शिक्षा में कुल नामांकनों में से भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 86 फीसद है। पाकिस्तान में 04, बांग्लादेश 07, नेपाल 02 फीसद व श्रीलंका सहित अन्य देशों में 01 फीसदी है।

जीडीपी के लिहाज से औसत खर्च

यूनेस्को और यूएनडीपी ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए जीडीपी का न्यूनतम 6 फीसद खर्च शिक्षा पर करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन किसी भी देश के लिए इस लक्ष्य को हासिल कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। भारत में यह दर कुल जीडीपी का करीब 3 से 3.5 फीसद, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में 2 से 2.5 फीसद है। नेपाल और मालदीव की स्थिति इससे बेहतर है।

नहीं मिला लाभ

शिक्षा में सुधार के लिए ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से निजीकरण हुआ लेकिन उसका लाभ दक्षिण एशियाई देशों के बहुसंख्यक छात्रों नहीं मिला। इसके बदले शिक्षा दो स्तरों में बंटकर रह गया। पहला सरकारी शिक्षा और दूसरा निजी स्कूलों व विश्वविद्यालयों की शिक्षा।

ग्लोबल ट्रेड

वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी में भारी कटौती, शिक्षा का कारपोराइजेशन, बैंकिंग लेन पर आधारित शिक्षा का ट्रेंड पर जोर है।

विजन डाक्यूमेंट तैयार

मास्सनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण भगत का कहना है कि प्रभावी शिक्षा नीति नहीं होने से वैश्व रैंकिंग में भारत की स्थिति खराब है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में 10 विश्वविद्यालयों को शामिल कराने का मिशन भी है। इस दिशा में शिक्षा नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

